SHRI M. ARUNACHALAM: I do not have the answer now. I will pass it on to the hon. Member as soon as I get it.

DR. JOSEPH LEON D'SOUZA: He does not know the policy.

MR. CHAIRMAN: He is a new Minister. You must be considerate.

SHRIMATI MAIMOONA SULTAN:*

MR. CHAIRMAN: Nothing will be recorded.

SHRIMATI MAIMOONA SULTAN:*

MR. CHAIRMAN: You cannot make such statements. Prof. Ramachandra Rao please.

PROF. B. RAMACHANDRA RAO: Sir, in response to a similar question on the 18th November, 1985, the Minister has answered that no final view was taken on this matter regarding the findings of the team which was appointed for on the spot assessment. This was nearly one year ago. I would like to know how long the Ministry will take to give a final view on this report.

SHRI M. ARUNACHALAM: What is the question?

MR. CHAIRMAN: How long will it take for you to give a final decision on the report?

SHRI M. ARUNACHALAM: The panel has given the report.

PROF. B. R. RAMACHANDRA RAO: How long will you take?

MR. CHAIRMAN: Say, as soon as possible.

SHRI M. ARUNACHALAM: It is under consideration.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Mr. Chairman, you are putting the question and you are giving the answer also. Well, we can do with the Chairman.

*Not recorded as ordered by the Chair.

SHRI M. ARUNACHALAM: Sir, it is under consideration.

SHRI SURESH KALMADI: The senior Minister is there. He should bear him out.

SHRI VISHVAJIT PRITHVIJIT SINGH: Mr. Chairman, Sir, I would like to refer to the statement given by the Minister in which he mentions Baralgan Ketone is one of the drugs being manuractured by M|s. Hoechst. He has given the permitted licence capacity and the production figures for the years 1982-83, 1983-84 and 1984-85. He also says that the state of its manufacture is basic. I would like to know from the Minister, in view of the fact that M|s. Hoechst is charging nearly Rs. 24,000 a kilo as opposed to the Government notified price of Rs. 1800 a kilo and it has been doing so for the last 10 years, what is the present position regarding proceedings against M|s. Hoechst, what are the steps being taken and is the court case being followed up? What is going to happen in this case?

SHRI M. ARUNACHALAM: I have already answered this question. The case is *sub judice*.

SHRI SURESH KALMADI: The Minister should do the home work. The new Ministers are not doing the home work, this is what we are seeing for the last two weeks.

SHRI K. MOHANAN: I propose that there should be an intensive training course for the new Ministers.

पन-बिजली की उत्पादन लागत

*191. श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :†
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1982-83 के वर्ष के वार्षिक लेखाओं के अनुसार बिहार और पंजाब में पन-बिजली की उत्पादन लागत

†सभा में यह प्रश्न श्री प्यारे लाल डेलवाल द्वारा पूछा गया।

क्रमश: 42.99 पैसे था 5.44 पैसे प्रति यूनिट थी और ताप बिजली की उत्पादन लागत तमिलनाडु तथा उड़ीसा में क्रमश: 61.88 पैसे और 22.69 पैसे प्रति यूनिट थी ;

(ख) यदि हां, तो कुछ राज्यों में बिजली उत्पादन की लागत कई गुणा अधिक होने के कारण क्या हैं और इसमें कमी लाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) प्रत्येक राज्य में पन तथा तापीय बिजली की वर्तमान उत्पादन लागत तथा उनकी औसत टैरिफ दर का ब्यौरा क्या है ;

(घ) विभिन्न राज्यों में उत्पादित की जा रही परमाणु बिजली की उत्पादन लागत व टैरिफ से इसकी तुलनात्मक स्थिति क्या है ; और

(ङ) क्या योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में विद्युत् मंडलों को लगभग 11750 करोड़ रुपए की हानि होने की संभावना है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ङ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) अलग-अलग राज्य में तथा अलग-अलग केन्द्र में विद्युत उत्पादन की लागत निम्नलिखित कारणों की वजह से भिन्न-भिन्न होती है ;

(1) परियोजना की पूंजी लागत ;

(2) संयंत्र की आयु ;

(3) क्षमता समुपयोजन ;

(4) केन्द्र का स्वरूप व्यस्ततम-कालीन् है अथवा भार पर आधाररित ।

(5) प्रचालन और अनुरक्षण खर्च; तथा

(6) स्थापना सम्बन्धी लागतें, आदि ।

केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों को सलाह दी है कि लागत में वृद्धियों को रोकने के लिए परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करें, क्षमता का इष्टतम उपयोग करे तथा प्रचालन संबंधी खर्चों को कम करें । ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण और आधुनिकीकरण की एक स्कीम भी लागू की गई है ।

(ग) और (घ) 15 राज्य बिजली बोर्डों के सम्बन्ध में, जिनके लेखे उपलब्ध हैं, 1983-84 में जल विद्युत् और ताप विद्युत् केन्द्रों की विद्युत उत्पादन की लागत तथा टैरिफ की औसत दरें संलग्न अनुबंध में दी गई हैं । परमाणु विद्युत् केन्द्रों से बिजली बोर्डों को विद्युत् की बिक्री के लिए वर्तमान टैरिफ प्रति यूनिट 35 से 40 पैसे के बीच है ।

(ङ) जी, हां ।

अनुबन्ध

1983-84 के दौरान विद्युत उत्पादन (जल विद्युत् तथा ताप विद्युत्) की लागत और औसत टैरिफ

(आंकड़े पैसे प्रति यूनिट)

क्रम संख्या	राज्य बिजली बोर्ड	विद्युत् उत्पादन की लागत		औसत/टैरिफ
		ताप विद्युत्	जल विद्युत्	
1	आन्ध्र प्रदेश	33.55	6.79	47.1
2	बिहार	48.01	33.15	65.7
3	गुजरात	38.85	6.56	67.9
4	हरियाणा	77.59	8.22	44.6
5	हिमाचल प्रदेश	—	11.68	36.4
6	कर्नाटक*	—	6.32	39.1
7	केरल	—	8.15	30.0
8	मध्य प्रदेश	31.57	8.98	58.2
9	महाराष्ट्र	40.37	5.84	49.9
10	उड़ीसा	22.69	6.93	45.1
11	पंजाब	51.1	5.80	34.2
12	राजस्थान	34.80	8.45	48.2
13	तमिलनाडु	70.55	15.08	44.7
14	उत्तर प्रदेश	56.24	17.40	51.4
15	पश्चिम बंगाल	30.37	30.29	61.4

*1982-83 के लेखों पर आधारित। 1983-84 के लेखों की अभी तक लेखा परीक्षा नहीं की गई है

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : अध्यक्ष जी, सरकार ने जब उत्तर दिया है, उसमें इस बात को स्वीकार किया गया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने इस बात को स्वीकार किया है कि 11750 करोड़ रुपए का नुकसान विद्युत बोर्डों को होने की संभावना है, इतना बड़ा घाटा बिजली विभाग को होगा यह बात सरकार ने स्वीकार की है। साथ ही यह बात भी सही है कि बिजली विभाग का रख-रखाव और बाकी का जो खर्चा है, गड़बड़ी है, अव्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, उसके कारण बहुत सी योजनायें आज भी सरकार बिजली उत्पादन की पूरी नहीं कर पायी है। मैं माननीय मंत्री जी से यह बात पूछना चाहता हूं कि यह जो सरकार ने "क" और "ख" में उत्तर दिये हैं, जिसमें इस बात को स्वीकार किया है कि जल-विद्युत् के उत्पादन में ताप विद्युत् के मुकाबले काफी कम उत्पादन लागत आती है और यह आंकड़े भी दिए गए हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि कितनी प्रदेश सरकारों ने जल-विद्युत् योजनाओं की स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार के पास योजनायें भेजी हैं और उनमें से किन-किन जल विद्युत् योजनाओं को केन्द्र सरकार ने अभी तक स्वीकृति प्रदान की है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : श्रीमन्, यह प्रश्न था---विभिन्न बिजली बोर्डों के द्वारा चलाये जा रहे पानी और ताप-विद्युत् बिजलीघरों में जो जनरेशन कोस्ट हैं; उसमें आने वाले अन्तर का। इसमें माननीय सदस्य ने अपने मूल प्रश्न में उन

योजनाओं के बारे में नहीं पूछा था, जो सी० ए० के पास क्लीयरेंस के लिए आयी हुई हैं । श्रीमन् अगर आपका निर्देश हो तो मैं यह सूचना इकट्ठी करके दे सकता हूं । वैसे यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है । मेरे कहने का मतलब यह था । लेकिन अगर आपका निर्देश होगा तो मैं सूचना माननीय सदस्य को भिजवा दूंगा ।

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : सभापति जी . . .

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Projects undertaken by the E.P.I. Ltd.

*181. SHRI SUKOMAL SEN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that out of about 105 projects completed by the Engineering Projects (I) Ltd., so far only two projects were unprofitable and that too due to some unfavourable terms accepted by the E.P.I. top Management; and

(b) if so, what are the deatils thereof; and whether the performance record of the E.P.I. has been satisfactory?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) The Engineering Projects (India) Limited has incurred losses mainly on their two overseas projects *i.e.* Al-Firdous Housing Project, Kuwait and Council of Ministers Building Project, Iraq. The main reasons for the losses are heavy escalation in prices during implementation of the projects; rigid attitude of the clients in the matter of acceptance of works, settlement of claims and release of outstanding heavy interest burden and guarantee charges; onset of conflict between Iran and Iraq; and declining order book position due to severe competition etc.

The company is incurring large losses every year mainly on account of interest on overdrafts and Govt. loans. The financial results on current operations excluding interest on loans is quite satisfactory.

Shortage of Bus/Truck tyres

*183. SHRI M. KALAYANASUNDARAM: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have recently received representations from the All India Tyre Dealers' Federation, complaining about the shortage of bus/truck tyres and tubes and about the steep rise in their prices due to malpractices by the manufacturers;

(b) whether Government have since received the report of the Bureau of Industrial Costs and Prices (BICP) which was directed to investigate into tyre prices; and

(c) if so, what steps Government have taken so far in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) Except for temporary local shortages of bus/truck tyres reported from Bombay, Delhi and the North Eastern Region recently, there is no shortage of tyres in the country. Production of tyres is more than adequate to meet the current demand. However, the Automotive Tyres Manufacturers' Association have assured Government of adequate availability of tyres whenever reports of shortages are received by them are brought to their notice. The Developemnt Council for Tyres & Tubes, in which all concerned interests, including consumers, are represented, also reviews production, distribution and prices of tyres.

There is no control on the prices or distribution of tyres at present. However, Government constantly reviews measures required to stabilise the prices of raw materials and other inputs as well as the incidence of indirect taxes so as to enable the tyre industry to maintain the prices at reasonable level. Import of automotive tyres has also been placed under open General Licence. Further, based on BICP Study, Government has referred the issue of prices, discounts and trade and distribution practices in the tyre industry for a probe by the MRTP Commission.